संविधान (एक सौ चारवां) संशोधन अधिनियम, 2019 के प्रवृत्त होने के बाद से, लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष प्रतिनिधित्व के उपबंध को आगे नहीं बढ़ाया गया है। कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में इस प्रकार वितरित की गई है कि प्रत्येक राज्य को आबंटित सीटों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या के मध्य अनुपात, जहां तक व्यवहार्य हो, सभी राज्यों के लिए समान रहे।